पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रथम अपील संख्या– 39/2022

= =

1. विनोद कुमार, उर्फ़ विनोद कुमार साही, पुत्र – स्वर्गीय गणेश प्रसाद साही, निवासी – ग्राम–चैनपुर, पोस्ट – चैनपुर, थाना – सिसवन, वर्त्तमान में, मोहल्ला –पॉल भवन, लाह बाजार, सलेमपुर , पोस्ट + थाना –छपरा टाउन, जिला –सारण, छपरा
2. श्रीमती. पुष्पा देवी पत्नी, विनोद कुमार उर्फ़ विनोद कुमार साही गाँव–चैनपुर के निवासी, पोस्ट – चैनपुर, थाना – सिसवन, जिला–सीवान, वर्तमान में निवासी मोहल्ला–पॉल भवन लाह बाजार, सलेमपुर, पोस्ट+ थाना– छापरा टाउन, जिला–सारण, छापरा
3. बिपुल कुमार पुत्र विनोद कुमार उर्फ़ बिनोद कुमार साही निवासी गाँव–चैनपुर, पोस्ट– चैनपुर, थाना– सिसवन जिला–सीवान, वर्तमान में निवासी मोहल्ला–पॉल भवन लाह बाजार, सलेमपुर, पोस्ट + थाना –छापरा टाउन, जिला–सारण, छापरा
4. विवेक कुमार, पुत्र– विनोद कुमार उर्फ़ बिनोद कुमार साही, निवासी ग्राम–चैनपुर, पोस्ट– सिसवन, जिला– सिवान, वर्त्तमान में, मोहल्ला –पॉल भवन, लाह बाजार, सलेमपुर, पोस्ट + थाना –छपरा टाउन, जिला –सारण, छपरा

= =

उपस्थिति:

अपीलार्थियों के लिए : श्री राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री संतोष कुमार वर्मा, अधिवक्ता

= =

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925—धारा 299—*अपीलकर्ता ने प्रोबेट मामले में अंतिम आदेश के खिलाफ प्रथम अपील दायर की—कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रोबेट कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ; और, इसलिए, कार्यवाही गैर–विवादास्पद थी—एक प्रोबेट कार्यवाही विवादास्पद हो जाती है यदि कोई प्रोबेट/प्रशासन के पत्र के अनुदान का विरोध करता प्रतीत होता है—कुशेश्वर के मामले में विद्वान डिवीजन बेंच ने माना कि विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ दायर अपील को नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाएगा जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI के साथ पठित धारा 96 के तहत विनियमित किया जाएगा—गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश एक डिक्री की तरह नहीं है—प्रोबेट केस को नीचे के विद्वान न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था*

क्योंकि वसीयत/विल को वास्तविक और संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त नहीं पाया गया था—अंतिम आदेश भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत अपील योग्य आदेश है, इसलिए, ऐसी अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII के साथ पठित धारा 104 के तहत विनियमित करने के लिए विविध अपील के रूप में माना जाना आवश्यक है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में अंतिम आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 384 के तहत अपील की तरह—कार्यालय/स्टाम्प रिपोर्टर ने प्रथम अपील की विचारणीयता के बारे में आपत्ति उठाई है जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता का उचित उपाय विविध अपील दायर करने में निहित है—कार्यालय/स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा उठाई गई आपत्ति को बरकरार रखा गया—अपीलकर्ता को प्रथम अपील को विविध अपील के रूप में बदलने की स्वतंत्रता है। (पैरा 22 से 25)

2017 (3) पी.एल.जे.आर. 791; 2009 (3) पी.एल.जे.आर. 990 (एफ.बी.); 2013 (1) पी.एल.जे.आर. 176; 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन कर्नाटक 409—संदर्भित किया गया

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

= =

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार
सीएवी निर्णय
(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)
तिथीः– 19–02–2024

माननीय एकल न्यायाधीश के संदर्भ पर इस पीठ को यह मामला प्राप्त हुआ है। यह संदर्भ इस तथ्य की पृष्ठभूमि में दिया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 के तहत विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश– पंचम, सारण, छपरा के 2017 का प्रोबेट मामला संख्या 37 वाली गैर–विवादास्पद कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक–22.02.2022 को वर्तमान अपील मे चुनौती दी गई है जिसमें तहत अपीलार्थी द्वारा दायर प्रोबेट याचिका खारिज कर दी गई है। कार्यालय ने वर्तमान अपील की पोषणीयता के बारे में यह देखते हुए कि विवादित आदेश के खिलाफ माननीय खण्डपीठ के फैसले **कुशेश्वर पूर्बे बनाम श्री श्री 108 राम जानकी जी एस. और अन्य (1998 की पहली अपील–633) जैसा कि 2017 (3) पी. एल. जे. आर. 791** को देखते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 के तहत विविध अपील दायर करने का उचित उपाय सूचित करते हुए आपत्ति जताई है ।

2. माननीय एकल न्यायाधीश का विचार है कि माननीय खण्डपीठ ने **कुशेश्वर पुरबे मामले**(ऊपर) में गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डाला है। इसलिए, प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण के लिए संदर्भित किया गया है।

3. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता हैः–

i) क्या गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत दायर अपील को आदेश XLI के साथ पठित धारा 96 के तहत नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाना चाहिए या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII के साथ पठित धारा 104 के तहत विविध अपील के रूप में माना जाना चाहिए।

4. हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

5.अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के वैधानिक प्रावधानों को देखते हुए गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत अपील को भी नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाना चाहिए। वह **कुशेश्वर पूर्बे मामले** (उपरोक्त) का भी उल्लेख करते है जिसमें माननीय खण्डपीठ ने गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत दायर ऐसी अपील के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया है।

6. हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

7. हम पाते हैं कि मामला विद्वान अधिवक्ता को **कुशेश्वर पूर्बे मामले**(ऊपर) में खंड पीठ में **केवला देवी जितेन्द्र एवं अन्य श्री कृष्ण देवी और अन्र. [2013 (1) पी. एल. जे. आर. 176],** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 और अधिनियम की धारा 384 (2) के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील के वर्गीकरण के संबंध में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त संदेह के प्रकाश में भेजा गया था।

8. उपरोक्त संदेह माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा **केवाला देवी मामला** (सुप्रा)**सुनीता कुमारी बनाम प्रेम कुमार [2009 (3) पी. एल. जे. आर. 990]**मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के आलोक में व्यक्त किया गया था, जिसमें एल. पूर्ण पीठ ने परिवार न्यायालय अधिनियम और उसमें प्रदान की गई प्रक्रिया और परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील के प्रावधान पर चर्चा करने के बाद कहा कि परिवार न्यायालयों की धारा 19 के तहत दायर अपील को डिक्री के खिलाफ अपील के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, उन्हें प्रथम अपील के बजाय विविध अपील के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि, माननीय एकल न्यायाधीश ने सुनीता कुमारी मामले (सुप्रा) के फैसले के प्रकाश में अपना विचार व्यक्त किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत दायर अपीलों को भी विविध अपील के रूप में माना जाना चाहिए। कुशेश्वर पूर्बे मामले के अवलोकन के बाद, हम पाते हैं कि माननीय खण्डपीठ ने **मिस प्रेसी पिंटो बनाम रॉनी मैक्सिम पिंटो और अन्य (2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 409)**सहित वैधानिक मामलों और केस विधि पर चर्चा करने के बाद खंडपीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

"14. तथापि, यह स्पष्ट है कि सुनीता कुमारी मामले में पूर्ण पीठ द्वारा विचार के लिए जो विवाद आया था, वह परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत पारित एक आदेश की प्रकृति से संबंधित था, जिसे उसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट विवादों के निर्णय के लिए अधिनियमित किया गया है और ऐसे विवाद/मामले के निर्धारण के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसलिए, हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि सुनीता कुमारी (उपरोक्त) में निर्धारित कानून एक आदेश के खिलाफ अपील के लिए प्रदान किए गए सभी वैधानिक प्रावधानों पर सामान्य रूप से लागू होगा।

... ...

18. प्रेसी पिंटो (ऊपर) में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए हमें राजी नहीं किया गया है। हम उक्त मामले में पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत अपील के वर्गीकरण के संबंध में केवल देवी (उपरोक्त) पर सही निर्णय नहीं लिया गया है। तदनुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हुए संदर्भ का उत्तर देते हैं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत एक विवादास्पद कार्यवाही का अंत में निपटान करने वाली अपील, जैसा कि धारा 295 के तहत परिकल्पित है, को नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाएगा और ऐसी अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 (2) के तहत दायर अपील को विविध माना जाएगा और ऐसी अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा संचालित होगी।

9. इस प्रकार, यह प्रकट करता है कि **कुशेश्वर पूर्व मामले**(उपरोक्त) में, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 299 के तहत अपील के मामले में प्रक्रिया के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में अंतिम आदेश के खिलाफ जहाँ तक विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में अंतिम आदेश के खिलाफ अपील के मामले में प्रक्रिया के बारे में निर्णय का संबंध है, माननीय खण्डपीठ द्वारा दिया गया निर्णय से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह की अपील को नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाएगा। यहां तक कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 के तहत दायर अपील की प्रक्रिया के बारे में निर्णय भी स्पष्ट है कि ऐसी अपील को विविध अपील माना जाएगा।

10.इसलिए, माननीय एकल न्यायाधीश ने गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत दायर अपील के मामले

में प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण के लिए मामला भेजा है। हालाँकि, इससे पहले कि हम गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में अंतिम आदेश के खिलाफ अपील में प्रक्रिया के बारे में अपनी राय व्यक्त करें, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और मामले के कानूनों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

11.इस बात में कोई विवाद नहीं है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एक विशेष कानून है। हालांकि, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के साथ–साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 268 को देखते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रावधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही पर इस हद तक लागू होता है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधानों के विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

12.सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 इस प्रकार है –

> "**4. व्यावृत्ति–** (1) इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, इस संहिता की कोई भी बात वर्तमान में लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष क्षेत्राधिकार या प्रदत्त शक्ति या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।

13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 268 को इस प्रकार पढ़ा जाए:–

> "**268. प्रोबेट और प्रशासन के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाही–** प्रोबेट और प्रशासन के पत्र देने के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियों को, जैसा कि इसके बाद अन्यथा प्रदान किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियमित किया जाएगा।"

14.भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के आलोक में, हम आगे पाते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जिला न्यायाधीश के प्रत्येक आदेश से उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। धारा 299 इस प्रकार है:

> "**299. जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील–** प्रत्येक जिला न्यायाधीश द्वारा उसे एतद् द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किया गया आदेश अपीलों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील के अधीन होगा।"

15.हम आगे पाते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में दो प्रकार की अपीलें हैं–मूल फरमानों के खिलाफ आदेश 41 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 96 के तहत नियमित पहली अपील और निर्दिष्ट अपील योग्य आदेशों के खिलाफ आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 104 के तहत विविध अपील। धारा 96 इस प्रकार हैः

> "**96. मूल डिक्री से अपील–** (1) कहाँ सहेजें अन्यथा स्पस्ट रूप से इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत अपील, मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री से ऐसे न्यायालय के निर्णयों से अपील सुनने के लिए अधिकृत न्यायालय में होगी।
>
> (2) एकतरफा पारित मूल डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।
>
> (3) न्यायालय द्वारा पारित आदेशक विरुद्ध ।
>
> (4) लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय प्रकृति के किसी भी मुकदमे में डिक्री से कानून के प्रश्न के अलावा कोई अपील नहीं होगी। जब मूल वाद की विषय वस्तु की राशि या मूल्य दस हजार रुपये से अधिक न हो।

16. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 में कहा गया है, जो इस प्रकार हैः

"**104. आदेश जिनसे अपील की जाती है–** (1) एक अपील निम्नलिखित आदेशों से निहित होगा, और इस संहिता के मुख्य भाग में या कुछ समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए आदेशों को छोड़कर, कोई अन्य आदेश नहीं होगाः

(एफ. एफ.) धारा 35 ए के तहत एक आदेश;

(एफ. एफ. ए.) और धारा 91 या धारा 92 के तहत आदेश जो धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति का मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से इनकार करता है, जैसा भी मामला हो;

(जी) धारा 95 के तहत एक आदेश;

(एच) इस संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत जुर्माना लगाने या किसी भी व्यक्ति की नागरिक जेल में गिरफ्तारी या निरोध का निर्देश देने वाला आदेश, सिवाय इसके कि जहां ऐसी गिरफ्तारी या निरोध एक डिक्री के निष्पादन में है;

(आई) नियमों के तहत किया गया कोई आदेश जिससे नियमों द्वारा अपील की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हैः

बशर्ते कि खंड (एफ. एफ.) में निर्दिष्ट किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील इस आधार पर नहीं होगी कि कोई आदेश या कम राशि के भुगतान के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।"

(जोर दिया गया)

17. आदेश 43 नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नानुसार हैः

"**1. आदेशों से अपील–** एक अपील धारा 104 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेशों से होगी, अर्थात्ः

(ए) आदेश VII के नियम 10 के तहत एक आदेश जो उचित न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली शिकायत को लौटाता है, सिवाय इसके कि जहां आदेश VII के नियम 10 ए में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया है;

(सी) आदेश IX के नियम 9 के तहत एक आदेश जो एक मुकदमे को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन (अपील के लिए खुले मामले में) को अस्वीकार करता है;

(डी) एकतरफा पारित डिक्री को ख़ारिज करने के लिए एक आवेदन (अपील के लिए खुले मामले में) आदेश को अस्वीकार करने वाले आदेश IX के 13 के लिए नियम के तहत एक आदेश;

(एफ) आदेश XI के नियम 21 के तहत एक आदेश;

(आई) किसी दस्तावेज़ के मसौदे या अनुमोदन पर आपत्ति पर आदेश XXI के नियम 34 के तहत एक आदेश;

(जे) आदेश XXI के नियम 72 या नियम 92 के तहत एक आदेश जिसमें बिक्री को अलग रखा गया है या अलग रखने से इनकार किया गया है;

(जे. ए.) आदेश XXI के नियम 106 के उप–नियम (1) के तहत किए गए आवेदन को अस्वीकार करने वाला आदेश, बशर्ते कि मूल आवेदन पर एक आदेश, यानी उस आदेश के नियम 105 के उप–नियम (1) में संदर्भित आवेदन अपील योग्य हो;

(के) आदेश XXII के नियम 9 के तहत एक आदेश जो किसी मुकदमे को कम करने या खारिज करने से इनकार करता है;

(एल) आदेश XXII के नियम 10 के तहत छुट्टी देने या देने से इनकार करने का आदेश;

(एन) आदेश XXV के नियम 2 के तहत एक आदेश जो एक मुकदमे को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन (अपील के लिए खुले मामले में) को अस्वीकार करता है;

(एन.ए.) आदेश XXXIII के नियम 5 या नियम 7 के तहत एक आदेश जो एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन को अस्वीकार करता है;

(पी) आदेश XXXV के नियम 3, नियम 4 या नियम 6 के तहत अंतर–अधिवक्ता–मुकदमों में आदेश;

(क्यू) आदेश XXXVIII के नियम 2, नियम 3 या नियम 6 के तहत एक आदेश;

(आर) नियम 1, नियम 2 8 [नियम 2 ए], नियम 4 या आदेश XXXIX के नियम 10 के तहत एक आदेश;

(एस) आदेश 40 के नियम 1 या नियम 4 के तहत एक आदेश;

(टी) आदेश 40 आई. के नियम 19 के तहत फिर से स्वीकार करने से इनकार करने का आदेश, या आदेश 41 के नियम 21 के तहत फिर से सुनवाई करने के लिए, एक अपील;

(यू) नियम 23 के तहत एक आदेश या आदेश 41 के नियम 23 ए के तहत एक मामले को फिर से भेजने का आदेश, जहां अपील अपीलीय न्यायालय की डिक्री से होगी;

(डब्ल्यू) आदेश 47 के नियम 4 के तहत एक आदेश जो समीक्षा के लिए एक आवेदन प्रदान करता है।

18.यहाँ यह इंगित करना उचित है कि धारा 104 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, अपील न केवल इस धारा के तहत निर्दिष्ट आदेशों के खिलाफ है, बल्कि ऐसे आदेशों के खिलाफ भी है जिनके खिलाफ अपील "कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा"प्रदान की गई है। हम पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 में प्रत्येक आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है। अपीलों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत अपील के इस सामान्य प्रावधानों के कारण, अपीलों की प्रकृति के बारे में विवाद उत्पन्न हुआ है–क्या ऐसी अपीलों को सिविल प्रक्रिया संहिता. के आदेश 41 के साथ पठित धारा 96 के तहत विनियमित नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाना चाहिए या आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 104 के तहत विनियमित विविध अपील के रूप में माना जाना चाहिए।

19.हम पहले ही पा चुके हैं कि कुशेश्वर पुरबे मामले (उपरोक्त) में माननीय खंड पीठ ने पहले ही फैसला सुनाया है कि विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश को आदेश 41 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 96 के तहत विनियमित नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाना चाहिए और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 के तहत अंतिम आदेशों के खिलाफ अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के तहत विनियमित विविध अपील के रूप में माना जाना चाहिए।

20.अब सवाल यह है कि क्या गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेशों के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत दायर अपीलों को भी नियमित प्रथम अपील या विविध अपील के रूप में माना जाना चाहिए। यहाँ, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 295 प्रासंगिक हो जाती है, जो उत्तर की कुंजी है। वह इस प्रकार हैः

> "295. **विवादास्पद मामलों में प्रक्रिया**–जिला न्यायाधीश के समक्ष किसी भी मामले में, जिसमें विवाद है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाहियां, जितना हो सके, एक नियमित मुकदमे का रूप लेंगी, जिसमें यथास्थिति, परिवीक्षा या प्रशासन के पत्रों के लिए याचिकाकर्ता वादी होगा, और जो व्यक्ति अनुदान का विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ है, वह प्रतिवादी होगा।

21.भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 295 के वैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि यदि प्रोबेट कार्यवाही विवादास्पद हो जाती है, तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, नियमित मुकदमे का रूप लेगा, जिसमें याचिकाकर्ता वादी होगा और जो व्यक्ति अनुदान का विरोध करता हुआ दिखाई देगा, वह प्रतिवादी होगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 286 के स्पष्टीकरण के अनुसार, एक प्रोबेट कार्यवाही विवादास्पद हो जाती है यदि कोई प्रोबेट/प्रशासन पत्र के अनुदान का विरोध करता है। इस प्रकार, विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश को एक डिक्री की तरह माना जाता है, हालांकि यह शब्द के सख्त अर्थों में एक डिक्री नहीं है। इसलिए। **कुशेश्वर पुरबे मामले** (उपरोक्त) में माननीय खंड पीठ ने निर्णय दिया है कि विवादास्पद परिवीक्षा कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ दायर अपील को आदेश 41 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 96 के तहत विनियमित की जाने वाली नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाएगा।

22. गैर–विवादास्पद परिवीक्षा कार्यवाही के मामले में, इसे नियमित मुकदमे का रूप लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश एक डिक्री की

तरह नहीं है। यह केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत एक अपील योग्य आदेश है, और इसलिए इस तरह की अपील को आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 104 के तहत विनियमित करने के लिए विविध अपील के रूप में माना जाना आवश्यक है, जैसा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में अंतिम आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 के तहत प्रदान की गई अपील है। **कुशेश्वर पूर्बे** मामले (उपरोक्त) में इस अदालत की माननीय खंड पीठ ने पहले ही निर्णय दे दिया है, जैसा कि हमने देखा है, कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 के तहत दायर अपील को विविध अपील के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित कार्यवाही भी कभी भी नियमित मुकदमे का रूप नहीं लेती है। इस तरह की कार्यवाही धारा 373 के अनुसार संक्षिप्त प्रकृति की होती है जो स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि जिला न्यायाधीश को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर संक्षिप्त तरीके से निर्णय लेना आवश्यक है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 373 और 384 इस प्रकार हैः

> "**373. आवेदन पर प्रक्रिया–** (1) अगर जिले में न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन पर विचार करने का आधार है, वह उसकी सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित करेगा और आवेदन की और सुनवाई (ए)के लिए निर्धारित दिन की सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे न्यायाधीश की राय में आवेदन की विशेष सूचना दी जानी चाहिए, और
>
> (बी) न्यायालय के किसी विशिष्ट भाग पर चिपकाया जाए और इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, यदि कोई अन्य तरीके से प्रकाशित किया जाए, और निर्धारित दिन पर, <u>या उसके तुरंत बाद, प्रमाण पत्र के अधिकार पर संक्षिप्त तरीके से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।</u>
>
> (2) जब न्यायाधीश आवेदक का अधिकार तय करता है, तो न्यायाधीश उसे प्रमाण पत्र देने का आदेश देगा।
>
> (3) यदि न्यायाधीश कानून या तथ्य के प्रश्नों का निर्धारण किए बिना प्रमाण पत्र के अधिकार का निर्णय नहीं ले सकता है जो संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारण के लिए बहुत जटिल और कठिन प्रतीत होते हैं, फिर भी वह आवेदक को एक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है यदि वह इसके लिए प्रथम दृष्टया सबसे अच्छा शीर्षक रखने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है।
>
> (4) जब प्रमाण पत्र के लिए एक से अधिक आवेदक होते हैं और न्यायाधीश को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे एक से अधिक आवेदक मृतक की संपत्ति में रुचि रखते हैं, तो

न्यायाधीश, यह तय करने में कि प्रमाण पत्र किसे दिया जाना है, अन्य मामलों में आवेदकों की रूचि और योग्यता की सीमा को ध्यान में रख सकता है।

384. अपील — (1) इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस भाग के तहत प्रमाण पत्र देने, अस्वीकार करने या निरस्त करने के जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, और उच्च न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो अपील पर अपने आदेश द्वारा, उस व्यक्ति की घोषणा कर सकता है जिसे प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और जिला न्यायाधीश को, इसके लिए आवेदन किए जाने पर, पहले से ही दिए गए प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के अधिक्रमण में, तदनुसार इसे देने का निर्देश दे सकता है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत अपील के लिए अनुमत समय के भीतर उप–धारा (1) के तहत अपील की जानी चाहिए।

(3) उप–धारा (1) के प्रावधानों और उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश और संशोधन के प्रावधानों और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के निर्णय की समीक्षा के संबंध में, जैसा कि उस संहिता की धारा 141 द्वारा लागू किया गया है, इस भाग के तहत जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

(जोर दिया गया)

23. वर्त्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने प्रोबैट मामला संख्या 37/2017 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पंचम सारण छपरा द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 22.02.2022 के खिलाफ 2022 की प्रथम अपील संख्या 39 दायर की है। इस प्रोबैट कार्यवाही में, सामान्य उद्धरणों के बावजूद, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और इसलिए कार्यवाही गैर–विवादास्पद थी। हालाँकि, विवादित आदेश द्वारा, अपीलार्थी के प्रोबेट मामले को खारिज कर दिया गया था क्योंकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक और संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त वसीयत नहीं पाई गई थी। चूंकि अपील प्रथम अपील के रूप में दायर की गई है, कार्यालय ने अपील की पोषणीयता के बारे में आपत्ति जताई है, यह देखते हुए कि अपीलार्थी का उचित उपचार विविध अपील दायर करने में निहित है। इसलिए, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसी अपील के मामले में प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ दिया गया है |

24. उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम उस संदर्भ का जवाब देते हैं जिसमें कहा गया है कि गैर–विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत दायर की गई याचिका को विविध अपील के रूप में

माना जाना चाहिए, जो आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 104 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अधीन है।

25.तदनुसार, हम कार्यालय/स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा उठाई गई आपत्ति को बरकरार रखते हैं कि वर्तमान अपील में, अपीलार्थी को विविध अपील के रूप में अपील दायर करनी चाहिए थी न कि प्रथम अपील के रूप में। अपीलार्थी अभी भी प्रथम अपील को विविध अपील के रूप में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र है। कार्यालय को अभिलेख को माननीय एकल न्यायाधीश को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है। ताकि वह मामले को आगे बढ़ाए जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

एस.अली/चन्दन/
रमेश–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।